



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

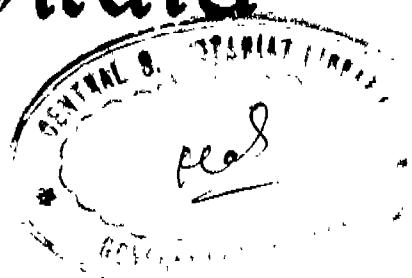
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 2001/कार्तिक 7, 1923

No. 546]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 2001/KARTIKA 7, 1923



बस्त्र भंगालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2001

[संशोधित पटसन विनिर्मिति विकास परिषद (प्रक्रियात्मक) नियम, 1984 के लिए अधिसूचना]

सा.का.नि. 808 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पटसन विनिर्मिति विकास परिषद अधिनियम, 1983 (1983 का 27) की धारा 25

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमों में संशोधन करती है। संशोधित नियम मिलानुसार होंगे :—

- (1) संक्षिप्त नामः— इन नियमों का संक्षिप्त नाम पटसन विनिर्मिति विकास परिषद (प्रक्रियात्मक) नियम (संशोधन), 2001 है।
- (2) नियम 3 (घ)ः— "सचिव" से परिषद के सचिव के कृत्यों को करने के लिए इन नियमों के नियम 6 के अधीन नियुक्त परिषद का सचिव-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है।
- (3) नियम 4(1)ः— अधिनियम और उसके अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष परिषद की बैठकों का सभापतित्व करेगा।
- (4) नियम 6(1)ः— सचिव की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।
नियम 6(2)ः— सचिव परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और अध्यक्ष के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।
नियम 6(3)ः— सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह :—
- (iv) परिषद द्वारा किए गए कामकाज का अभिलेख रखने वाली कार्यवृत्त अनुरक्षित करे और अगले अधिवेशन की पुष्टि के लिए इस कार्यवृत्त को सदस्यों को परिचालित करें।
- (5) नियम 11(1)ः— परिषद की सदस्यता में किसी भी कारण से होने वाली किसी आकस्मिक रिक्ति को इस रिक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

(6) नियम 12:- हटा दिया है ।
 (7) नियम 14(6):- परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से किन्तु उपस्थित कम से कम ग्यारह सदस्यों से परिषद के अधिवेशन में गणपूर्ति का गठन होगा ।

नियम 14(9):- परिषद द्वारा किए गए सभी कामकाज का अभिलेख बनाए रखा जाएगा और ऐसे अभिलेखों को अगले अधिवेशन की पुष्टि के लिए सदस्यों को परिचालित किया जाएगा । परिषद के अधिवेशन में किए गए कामकाज के अभिलेख पर ऐसे अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(8) नियम 16(1):- नियुक्ति की शक्ति- अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिषद ऐसे नये पद सृजित कर सकेगी और उसमें नई नियुक्तियां कर सकेगी जो उसके कार्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो, परंतु 13,500 रु. प्रति मास से अधिक के अधिकतम वेतन वाले कोई पद केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना न तो सृजित किए जाएंगे और न भरे जाएंगे ।

नियम 16(2)(1):- नियम 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिषद अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में निधि से किसी व्यय को संकल्प द्वारा मंजूर कर सकेगी या ऐसी संविदा कर सकेगी जिसमें वह व्यय निहित हों :

परंतु परिषद बजट प्रावक्कलन से अधिक कोई व्यय मंजूर नहीं करेगी या कोई ऐसी संविदा नहीं करेगी जिसमें वह व्यय अंतर्वलित है :

परंतु यह और कि परिषद केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, ऐसा कोई संविदा नहीं करेगी जिसमें पच्चीस लाख रुपये से अधिक का व्यय अंतर्वलित है या जो पांच वर्ष की कालावधि तक का है ।

नियम 16(2)(II):- परिषद को परिसंपत्ति की सामान्य टूट-फूट (मूल्य छास के बदले में) से हुई सभी हानियों और किसी व्यक्तिगत मामले में पच्चीस हजार रुपए तक हानियों को माफ करने की शक्ति होगी ।

नियम 16(2)(III):- परिषद विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों अथवा अन्य प्रासंगिक विनियमों और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन प्रत्येक व्यक्तिगत मद पर अनुमति योग्य एक राशि तक भारत के बाहर व्यय उपगत कर सकती है ।

नियम 19(2):- परिषद द्वारा या उसकी ओर से सभी संदाय सचिव की विशेष स्वीकृति के अधीन ऐसी रकमों के सिवाय जो साधारणतया 5,000 रुपए और असाधारणतया 20,000 रु. से अधिक नहीं हैं, जिन्हें नकद रूप में दिया जा सकेगा, चैक द्वारा किए जाएंगे ।

नियम 19(6):- ऐसी सभी निधियां जो चालू व्यय के लिए अपेक्षित नहीं हैं, भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के उपयुक्त सावधि निष्केप में रखी जाएंगी ।

[फा. सं. 6/6/2000-पटसनि निर्यात]

टी. नंदकुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2001

[A Notification to amend the Jute Manufactures Development Council (Procedural) Rules, 1984]

G.S.R. 808(E).—In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Jute Manufactures Development Council Act, 1983 (27 of 1983), the Central Government hereby amends the following rules. The amended rules will be as under :—

1. Short title :— These rules may be called the Jute Manufactures Development Council (Procedural) Rules (Amendment), 2001.
2. Rule 3(d) :— “Secretary” means the Secretary cum Chief Executive Officer of the Council appointed under rule 6 of these rules to carry on the functions of Secretary of the Council.
3. Rule 4(1) :— Subject to the provisions of the Act and the rules framed thereunder, the Chairman shall preside over the meeting of the Council.
4. Rule 6(1) :— The Secretary shall be appointed by the Central Government.

Rule 6(2) :— The Secretary shall be the Chief Executive Officer of the Council and shall work under the supervision of the Chairman.

Rule 6(3) :— It shall be the duty of the Secretary to :

(iv) maintain the minute books containing a record of the business transacted by the Council and get it circulated to the members for confirmation in the next meeting.

5. Rule 11(1) :— Any casual vacancy in the membership of the Council by any reason shall be filled by appointment by the Central Government within a period of three months from the date of arising such vacancy.
6. Rule 12 :— Deleted.
7. Rule 14 (6) :— One-third of the total number of members of the Council but not less than eleven members present shall form a quorum at a meeting of the Council.

Rule 14(9) :- A record shall be maintained of all business transacted by the Council. Copies of such record shall be submitted to the Central Government and circulated to the members for confirmation in the next meeting. The record of business transacted at a meeting of the Council shall be signed by the Chairman presiding over such meeting.

8. Rule 16(1) :- Power of appointment – Subject to the provisions of section 6 of the Act, the Council may create new posts and make appointments thereto as may be necessary for the efficient performance of its functions, provided that no posts carrying the maximum salary beyond Rupees 13,500 per mensem shall be created or filled without the previous approval of the Central Government.

Rule 16(2) (i) :- Subject to the provisions of rule 18, the Council may, by resolution, sanction any expenditure or enter into any contract involving expenditure from the Fund in the discharge of its functions under the Act :

Provided that the Council shall not sanction any expenditure or enter into any contract involving expenditure in excess of the budget allotments.

Provided further that the Council shall not enter into any contract involving any expenditures in excess of twenty five lakhs of rupees, or extending over a period of five years, without the previous approval of the Central Government.

Rule 16 (2) (ii) :- The Council shall have power to write off all the losses arising out of normal wear and tear of assets (in lieu of depreciation) and in other individual cases, losses upto twenty five thousand rupees.

Rule 16(2) (iii) :- The Council may incur expenditure outside India upto an amount, as may be permissible under the exchange control regulations or other relevant regulations, and guidelines of Govt. of India on each individual item.

9. Rule 19 (2) :- All payments by or on behalf of the Council shall be made by cheques except for amounts not exceeding ordinarily Rs. 5000/- and extraordinarily Rs. 20,000/- under special sanction of the Secretary, which may be paid in cash.

Rule 19 (6) :- All funds not required for current expenditure may be placed in suitable term deposit with State Bank of India or other Nationalised Banks.

[F. No. 6/6/2000-Jute Export]

T. NANDAKUMAR, Jt. Secy.